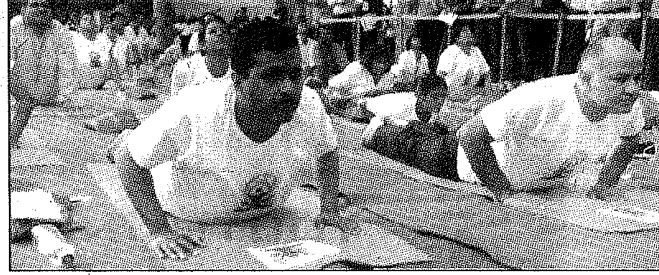


# केजरीवाल-जंग दूर, नजदीक आए बस्सी

नई दिल्ली, (कुमार गजेन्द्र): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अचानक योग कार्यक्रम में पहुंच कर सबको चौंका दिया। समझा जा रहा था कि केजरीवाल नरेन्द्र मोदी के इस कार्यक्रम नहीं जाएंगे। लेकिन केजरीवाल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ राजपथ पर अचानक योग कार्यक्रम में पहुंच गए। उधर इस कार्यक्रम में दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग भी मौजूद थे। लेकिन दोनों ही राजपथ की एक सड़क के इधर-उधर ही रहे। हाल के दिनों में दोनों के बीच कई मुद्दों पर टकराव देखने को मिला है। उधर दिल्ली पुलिस आयुक्त भीम सेन बस्सी जंग के नजदीक नजर आए।

केजरीवाल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मौजूद थे लेकिन दोनों ने जंग से दूरी ही बनाए रखी। हालिया टकराव को देखते हुए एक स्थान पर दोनों की मौजूदगी को लेकर लोगों में खासी दिलचस्पी थी। इस साल फरवरी में मुख्यमंत्री बनने के बाद प्राकृतिक उपचार करा चुके केजरीवाल सिसोदिया के साथ आसन करते देखे गए। जंग सड़क की दूसरी ओर बैठे थे, हालांकि इस दौरान उनकी केजरीवाल से मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा, 'योग को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिकता एकाग्रता के लिए है।' दिल्ली की आप सरकार ने योग दिवस के मौके पर किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया। उसने कहा था कि जब दिल्ली में एक बड़ा आयोजन हो रहा है तो फिर दूसरे की कोई जरूरत नहीं है।



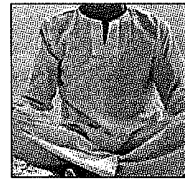
## अंधविश्वासी ट्वीट को लेकर घिरी बेदी

सीएम उम्मीदवार रहीं किरन बेदी को अंधविश्वास का एक ट्वीट महंगा साबित हुआ। एक ट्वीट की वजह से न केवल विवादों में घिरीं बल्कि उनकी सोशल मीडिया पर भी जमकर खिंचाई हुई। दरअसल दिल्ली में योग कार्यक्रम के उपरांत हुई बरसात पर किरन बेदी ने ट्वीट किया था कि लाखों लोगों के शांति, शांति, शांति के जाप से दिल्ली में प्री-मानसून की बौछरें पड़ीं। उनके मुताबिक यह योग के चमत्कार से हुआ।

## सीएम उपराज्यपाल से दूर योग करते रहे

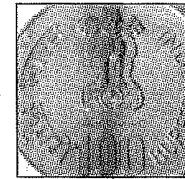
दिल्ली में चल रही अधिकारों की जंग रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भी नजर आई। एक ओर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल से दूर नजर आए तो वहीं दिल्ली के पुलिस आयुक्त उपराज्यपाल के करीब दिखाई दिए। केजरीवाल उपराज्यपाल से दूर योग करते रहे तो वहीं उपराज्यपाल के करीब पहुंचे पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने सियासी चर्चा बढ़ा दी।

## लांच हुआ विश्व का पहला योग सूट



भारत के एक गारमेंट ब्रांड ने विश्व का पहला योग सूट लांच किया है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें इस्तेमाल किया गया सिंथेटिक कभी त्वचा को स्पर्श नहीं करता और वस्त्र कभी शरीर को नहीं दबाते। इसे दो साल की रिसर्च के बाद डिजाइन किया गया है और इसे तैयार करने के लिए 11 देशों के योग शिक्षकों, टेक्सटाइल इंजीनियरों और योगप्रेमियों से सलाह-मशविरा किया गया।

## जारी हुए 10 और 100 के स्मारक सिक्के



मोदी ने 10 और 100 के स्मारक सिक्के जारी किए हैं। मोदी ने योग का व्यवसायीकरण नहीं करने का भी लोगों से आह्वान किया है। रविवार को उन्होंने कहा कि यह कोई कमोडिटी नहीं है और इस पर पूरी दुनिया का समान अधिकार है। पीएम ने समग्र स्वास्थ्य के लिए आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत करते हुए कहा कि योग दुनिया को जोड़ता है।

## केदारनाथ आपदा : अनसुलझे सवाल

केदारनाथ में आई बाढ़ और तबाही को दो साल पूरे हो चुके हैं। यद्यपि केदारनाथ धाम को तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया गया है, दिन-रात शंख ध्वनियां गूंजती हैं लेकिन अभी भी वहां मलबे से नरककाल मिल रहे हैं। पहाड़ों का क्रोध अभी भी कम नहीं हुआ है। पहाड़ दरकने की खबरें लगातार मिलती रहती हैं। इस वर्ष कुछ सुधार तो हुआ है लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। जून 2013 में हिमालय ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी आपदा देखी थी। केदारनाथ में आई बाढ़ में हजारों लोगों की जान गई थी। मौत का सरकारी आंकड़ा 6 हजार के आसपास है लेकिन सब जानते हैं कि उत्तराखंड में इससे कहीं अधिक लोगों की जान गई थी। क्षण भर में भव्य होटल, इमारतें, दुकानें सब मलबे में तब्दील हो गई थीं। करोड़ों की सम्पत्ति का नुक्सान हुआ था। जिन कारणों से प्राकृतिक आपदा आई थी, वे आज भी मौजूद हैं। न तो उत्तराखंड सरकार और न ही केन्द्र ने उन कारणों के निवारण के लिए ठोस कदम उठाए हैं। दो साल बाद भी कई सवाल हमारे सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा है जिसमें अदालत ने सरकार से पूछा था कि केदारनाथ त्रासदी में उत्तराखंड में बन रहे बांधों की क्या भूमिका है। केन्द्र सरकार इस सवाल को लगातार टालती रही है। इसी माह तीन जून को केन्द्र सरकार ने नई कमेटी बनाई जो केदारनाथ त्रासदी पर अब तक दी गई सारी रिपोर्ट की समीक्षा करेगी।

कोर्ट ने 2013 में सरकार को बांधों की भूमिका की जांच करने के आदेश दिए तो रवि चोपड़ा कमेटी बनाई गई जिसकी रिपोर्ट उत्तराखंड के बांधों के खिलाफ थी। कमेटी ने बांधों को खतरनाक बताया था और कहा कि प्राकृतिक आपदा में इन बांधों की बड़ी भूमिका थी। इसके बाद सरकार ने भी अदालत में कहा था कि बांध खतरनाक हैं लेकिन अब सरकार पलटी मार चुकी है। आपदा का मूल कारण था कि हमारी सरकारों द्वारा असंवेदनशील तरीकों से सड़क और हाइड्रो पावर योजनाएं बनाना है। भूगर्भ वैज्ञानिक के.एस. वाल्दिया के अनुसार इस क्षेत्र की चट्टानें नरम हैं। इनमें दरारें पड़ी हुई हैं। हल्की चोट से ही ये दरकने लगती हैं। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार पूर्व के भूकम्पों ने इस क्षेत्र के पहाड़ों को हिला दिया था, जिससे सामान्य वर्षा से ही ये दरकने लगे। उत्तराखंड के डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर के अनुसार सड़क निर्माण के लिए प्रयोग हो रहे विस्फोटकों के कारण पहाड़ ज्यादा गिरे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थापित एक्सपर्ट बाडी ने कहा है कि अधिकाधिक नुक्सान अलकनंदा एवं मंदाकिनी पर बन रही जल विद्युत परियोजनाओं के ऊपर और नीचे हुआ है। मंदाकिनी पर बन रही दो परियोजनाओं में 15 से 20 किलोमीटर तक सुरंगें निर्माणाधीन थीं। ये परियोजनाएं केदारनाथ के नजदीक बनाई जा रही हैं। इन सुरंगों को बनाने के लिए भारी मात्रा में विस्फोटकों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने पहाड़ों के जोड़ खोल दिए और ये पहाड़ दरक गए।

बांधों, नदियों और इंसानी जिन्दगी पर उनके प्रभाव का अध्ययन करने वाले पर्यावरणविदों का कहना है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार लोगों की जिन्दगी और गंगा के अस्तित्व से खिलवाड़ कर रही है। बांध कम्पनियों के मुनाफे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है। जो नई कमेटी बनी है उसमें कोई स्वतंत्र लोग नहीं हैं। बांधों का सवाल ऐसा सवाल है जो यह तय करेगा कि हिमालय के विकास की दिशा क्या होगी। भीषण तबाही के बाद लोगों की दिनचर्या सामान्य जरूर होने लगी है लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है कि केदारनाथ में दोबारा ऐसी आपदा नहीं आएगी। इसकी वजह पुनर्निर्माण को लेकर उत्तराखंड सरकार के इरादे और खड़े किए जा रहे ढांचे की मजबूती से इतर यह है कि कहीं प्रकृति फिर से अपना रौद्र रूप न दिखा दे। जिस राज्य के अफसरों, कर्मचारियों ने आपदा राहत के दौरान काम करने पर फर्जी बिल बनाकर लाखों-करोड़ों डकार लिए हों वहां के प्रशासन से कोई ज्यादा उम्मीद तो नहीं की जानी चाहिए। बुनियादी ढांचा किस तरह का हो? भावी जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में क्या किया जाए? ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। दो सालों में उत्तराखंड सरकार का सारा जोर केदारनाथ यात्रा शुरू कराकर वाहवाही लूटना था जबकि जोर इस बात पर होना चाहिए कि बढ़िया बुनियादी ढांचा तैयार करके आपदा प्रबंधन किया जाए। आपदा को हमेशा के लिए टालने वाला समाधान चाहिए, ऐसा सिर्फ केदारनाथ ही नहीं हर क्षेत्र में होना चाहिए। उत्तराखंड की प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने वाला विकास नहीं किया गया तो प्रकृति के कहर को कौन रोक सकेगा?

नैशनल इंस्टीट्यूट  
ऑफ डिजास्टर  
मैनेजमेंट के अनुसार  
पूर्व के भूकम्पों ने इस  
क्षेत्र के पहाड़ों को हिला  
दिया था, जिससे  
सामान्य वर्षा से ही ये  
दरकने लगे। उत्तराखंड  
के डिजास्टर मिटिगेशन  
एंड मैनेजमेंट सेंटर के  
अनुसार सड़क निर्माण  
के लिए प्रयोग हो रहे  
विस्फोटकों के कारण  
पहाड़ ज्यादा गिरे हैं।

—अश्विनी कुमार

## Welspun is Breaking Records at Wimbledon

**Shramana.Ganguly**  
@timesgroup.com

**Ahmedabad:** By the time Roger Federer and his rivals attempt to create history at the Wimbledon tennis championships, a textile factory in south Gujarat would have dispatched the classic green and purple towels that he and other male players will use during the tournament that begins June 29. The women's towel is styled in pink.

Federer's name might not ring a bell with the 7,000 workers at Welspun India Ltd's terry towel facility in Vapi but since 2010, they have been manufacturing the Wimbledon towels that have admirers both on the courts and off it. Federer has admitted to having at times packed away the coveted souvenir in his kit bag "because they make good gifts," while Andy Murray threw his into the crowd to celebrate victory in 2013.

"It is said that every third towel used is kept by the players or thrown to the viewing audience as a souvenir. Owing to its popularity, Wimbledon towels have a fan following of their own," said Dipali Goenka, MD, Welspun Global Brands Ltd and executive director of Welspun India.

IN-STORE PURCHASES

# 21% of retail sales influenced by digital: Deloitte report

BY SHRUTIKA VERMA  
shrutika.v@livemint.com

NEW DELHI

With the growing adoption of smartphones and greater number of Internet users in the nation, digital devices' influence on in-store purchases is expected to grow significantly, highlighting the need for retailers to adopt an omni-channel strategy, according to a report by consulting firm Deloitte Touche Tohmatsu India Pvt. Ltd.

The report, *Navigating the New Digital Divide*, released on Monday states that close to 21% of the total shopping in India, or ₹60,000 crore of in-store retail purchase, was influenced by digital devices including desktop computers, laptops, netbooks, smartphones and in-store devices such as payment kiosks, mobile payment device.

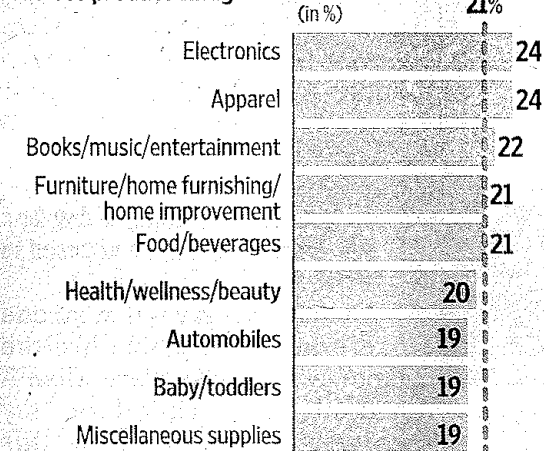
According to the report, India currently has more than 140 million smartphones, with the number estimated to grow to 500 million by 2020. Internet users are also estimated to grow to 600 million by 2020 from 300 million at present.

"Digital has become a preferred medium to research. Typi-

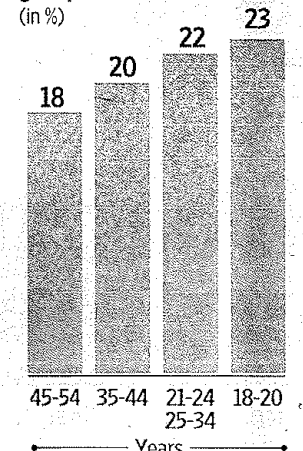
## DEVICE BOOST

Sixty-six per cent of shoppers end up spending more as a result of using digital devices, says a report by Deloitte India.

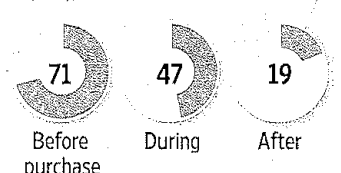
### Digital influence factor (DIF) across product categories



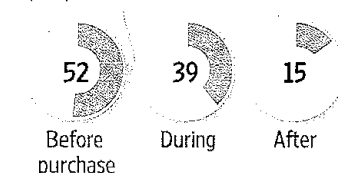
### Digital influence across age groups



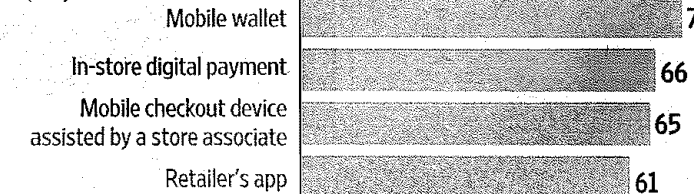
### Shoppers who use digital



### Social media usage



### Preference for digital payment options



Source: Deloitte  
NAVEEN KUMAR SAINI/MINT

cally, people used to walk in and discover products but now people walk in with digital discovery and we are seeing people use digital touchpoints post-buying as well to understand product features, etc.," said Rohit Bhatiani, director at Deloitte.

The report, which studied close to 2,000 urban Indian shoppers, said the conversion rate of shoppers who use a digital touchpoint is 40% higher than the non-digitally influenced

shoppers.

It said that 66% of shoppers end up spending more as a result of using digital devices. "38% shoppers were observed spending at least 25% more," according to the report. Digital information, reviews, recommendations and online discounts or coupons influence shoppers to spend more.

More than a third of digitally influenced shoppers would prefer the flexibility of buy-online-

pickup-in-store, the report said.

"The consumer today is not looking at channels differently. He would want the flexibility of buying and returning the products from any channel," said Bhatiani. "Today, 90% of the retailers do not have a mobile app or mobile-friendly websites and hence these retailers are not even considered by consumers for pre-buying research. Retailers need to create a strong meaningful digital presence to

attract customer attention," he added.

Digitally influenced shoppers tend to research for across-category purchases, with dominant categories being electronics, apparel, books, music and entertainment.

The report said facilitating a shopper's digital interaction within the store or otherwise increases the probability of conversion for a retailer by as much as 50%.

Another critical factor is social media. According to the report, 52% of shoppers use social media before buying, 39% during the buying process and 15% after shopping. "Social media is very important for retailers to not only make shoppers aware of their offerings but also to get their feedback and learn about new trends. A positive and responsive social presence needs to be an integral part of retailers' digital strategy," added Bhatiani.

The preference for using a digital medium for payments is also increasing among urban shoppers. Ninety-six per cent of digitally influenced shoppers are interested in using a digital device or touchpoint to make a payment in-store, as and when such payment options become available in the future, according to the report.

More than 70% of the users said they would prefer to use a mobile wallet, while 66% opted for in-store digital payment and 65% also wanted a mobile checkout device and help from a store assistant.

The survey polled a national sample of 2,006 consumers, with 42% in tier-I cities, 44% in tier-II and 14% in tier-III cities. Sixty-six per cent of the shoppers surveyed were male; 31% were in the 21-24 age group, 39% were aged 25-34 and 15% were 35-44 years old.



## Style tips to beat monsoon woes

**DON'T LET** the rainy season affect your desire to be stylish and fabulous. Opt for short dresses in light fabrics in bright colours to beat monsoon woes, says an expert.

Here are some monsoon fashion tips by experts:

**BRIGHT COLOURS:** It's time to wear all those bright colours from your wardrobe which you often sideline. Avoid wearing light colours like white and beige because they become transparent. Instead, flaunt bright colours like red, green, blue, indigo, yellow and stand out of the crowd.

**FABRICS:** Light fabrics like chiffon and silk are a big no in monsoons. Opt for fabrics which can dry out easily, need not require much maintenance and especially don't stick to your body. Cotton, linen and synthetic fabrics are a good option to carry on during monsoons. Just make sure they are not see-through anyway.

**BOTTOMS:** Carry bottoms which are



shorter in length rather than full-legged denims. Shorts, skirts, three-fourth trousers serve as better alternatives to the wet borders. A full-length jeans, trousers or skirts can leave you with damp ankles and legs.

**DRESSES:** Short dresses, frocks, maxi dresses and knee-length gowns can be perfect for monsoon. Avoid light colours that get dirty often. Also, avoid excessive fitted dress that makes your movements

stiff, uncomfortable. Prefer a knee-length dress of your favourite colour.

**PRINTS:** Last but not the least, shop for some printed clothes this monsoon. The bizarre zig-zags, linear creations or any other off the beat print can work out to give you an incredible yet adorable look of the season. IANS

